



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052025-262848  
CG-DL-E-02052025-262848

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1941]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2025/वैशाख 11, 1947

No. 1941]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2025/VAISHAKHA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजे अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2025

का.आ. 1985(अ).—यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य में शोलिंगनल्लूर, शोलिंगनल्लूर तालुक, चेन्नई जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संब्याक्त की थी। आ. 563(अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 152.665 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 13.297 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः तमिलनाडु राज्य सरकार ने उनके पत्र सं. 8795068/एमआईबी.1/2024-1 दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 के प्रत के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित अनधिसूचित भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार को वापस करने की आवश्यकता है;

और यतः विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 13.297 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है।

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 13.297 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 139.300 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संचया और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

### अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	602/3ए	14.96
2.	602/3बी	1.47
3.	602/3सी	1.43
4.	602/3डी	15
कुल		13.297
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		139.300

[फा. सं. एफ.2/4/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2025

**S.O. 1985(E).**—Whereas, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Sholinganallur, Sholinganallur Taluk, Chennai District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 152.665 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 563(E) dated 11<sup>th</sup> April, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 13.297 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No.8795068/MIB.1/2024-1 dated 5<sup>th</sup> December, 2024. Further, the land proposed for partial de-notification is needed back to Government of Tamil Nadu for Public purpose;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 13.297 hectares of the Special Economic Zone.

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 13.297 hectares**, thereby making resultant area as **139.300 hectares**. The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

**TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA**

Sl. No.	Survey No.	Area in hectares
1.	602/3A	14.96
2.	602/3B	1.47
3.	602/3C	1.43
4.	602/3D	15
<b>Total</b>		<b>13.297</b>
<b>Grand total area of SEZ after above de-notification</b>		<b>139.300</b>

[F. No. F.2/4/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.